

**अनुदान संख्या 22 – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय**  
**GRANT No. 22 - MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	2330,14,00	1537,63,97	-792,50,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			792,49,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	768,59,00	358,34,64	-410,24,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			410,24,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	112358.00	77793.64	77793.55
पु.	R.	-34564.36		
मुख्य शीर्ष “3601”	Major Head “3601”			
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	116588.00	72433.83	72433.79
पु.	R.	-44154.17		

(I) ₹3100.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – स्वायत्त परिषदों तथा संविधान की अनुसूची-VI के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अनुदान – स्वायत्त प्रादेशिक परिषद को विशेष विकास पैकेज” के अंतर्गत एक मामले में राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुई/हुआ:-

(का) “पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल को अंशदान” –

(क) “पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम” – ₹4649.08 लाख की बचत (₹25870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र कम प्राप्त होने तथा वित्तीय मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) “पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें” – ₹9463.09 लाख की बचत (₹29258.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने तथा कोविड-19 प्रतिबंध लगाए जाने के कारण नई परियोजनाएं न लेने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जाति आर्थिक विकास कल्याण” – ₹6407.72 लाख की बचत (₹15130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें” – ₹13997.23 लाख की बचत (₹42000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(I) Provision of ₹3100.00 lakhs remained unutilized in one case under Major Head “3601” - “Other Transfer/Grants to States - Grants to Autonomous Councils and areas covered under Schedule-VI of the Constitution - Special Development Package to Autonomous Territorial Council” - due to non-receipt of utilisation certificates from the State Governments.

(II) Under Major Head “2552” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Contribution to central resource pool for development of North Eastern Region” -

(a) “North East Special Infrastructure Development Scheme” - saving of ₹4649.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25870.00 lakhs) was due to less receipt of utilization certificates from the State Governments and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Schemes of North Eastern Council” - saving of ₹9463.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29258.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from the implementing agencies and non-taking up of new projects owing to imposition of COVID-19 restrictions.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Welfare of Scheduled Castes Economic Development” - saving of ₹6407.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15130.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub - Plan - Schemes of North Eastern Council” - saving of ₹13997.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42000.00 lakhs).

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड-19 महामारी के कारण उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई:-

(का) “पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों का केन्द्रीय पूल – पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के व्ययगत न होने वाले पूल से केन्द्रीय सहायता” – ₹17740.00 लाख की बचत (₹19324.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें” –

(क) “विशेष विकास परियोजना” – ₹2371.50 लाख की बचत (₹10372.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 प्रतिबंध लगाए जाने के कारण राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम के लिए ईएपी” – ₹5899.99 लाख की बचत (₹34000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए अव्ययगत संसाधनों के पूल से केन्द्रीय सहायता” – ₹3247.86 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates owing to COVID-19 restrictions and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head “3601” - “Other Transfer/Grants to States” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Pool of Resources for North East Region - Central Assistance from Non lapsable Pool of resources for North East and Sikkim” - saving of ₹17740.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19324.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificate from the State Governments.

(B) “Schemes of North Eastern Council” -

(a) “Special Development Project” - saving of ₹2371.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10372.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificate from the State Governments owing to imposition of COVID-19 restrictions.

(b) “EAP for North East Road Sector Development Scheme” - saving of ₹5899.99 lakhs (against the sectioned provision of ₹34000.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes-Central Assistance from Non lapsable Pool of resources for North East and Sikkim” - saving of ₹3247.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs); and

(D) “Tribal Area Sub-Plan” -



(I) ₹500.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “4552” के अंतर्गत, बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “सड़कें और सेतु – पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम” – ₹32488.10 लाख की बचत (₹46000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “सामान्य निर्माण – पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें – पूंजीगत” – ₹6362.25 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्र कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) “पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास – पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास” – ₹531.14 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण विकासात्मक कार्यकलाप शुरू न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1139.87 लाख की बचतें हुई; जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 96 प्रतिशत थीं।

(I) Provision of ₹500.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) Under Major Head “4552” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Roads and Bridges - North East Road Sector Development Scheme” - saving of ₹32488.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46000.00 lakhs); and

(B) “General Construction - Schemes of North Eastern Council - Capital” - saving of ₹6362.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs).

Saving under the above two heads were due to less receipt of utilization certificates from the implementing agencies owing to imposition of COVID-19 restrictions.

(C) “Integrated Development of Small and Medium Towns in NE Region - Integrated Development of Small and Medium Towns in NE Region” - saving of ₹531.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-taking up of developmental activities owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under three heads savings of ₹1139.87 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 15 percent to 96 percent of the sanctioned provision.